भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 252*

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 9 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन

252. श्रीमती रूपा गांगुली:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन को कार्यान्वित करने संबंधी कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या सरकार ने बैटरी संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान दल का गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

<u>विवरण</u>

"राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन" के संबंध मे श्रीमती रूपा गांगुली द्वारा पूछे गए दिनांक 09.08.2018 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.252 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग):

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान-2020 (एनईएमएमपी-2020) का वर्ष 2013 में शुभारंभ किया गया था। तत्पश्चात, एनईएमएमपी-2020 के तहत परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मार्च, 2015 में ₹795 करोड़ के परिव्यय के साथ फेम इंडिया स्कीम [भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण] अधिसूचित की गई थी।

2. यह स्कीम अब अपने अंतिम स्तर पर है और इसे दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। स्कीम के चरण-2 को अभी अनुमोदित किया जाना है।

3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने सूचित किया है कि चार (4) अनुसंधान समूह (इसरो, सीएसआईआर, एआरसीआई और आईआईटी मुंबई) लिथियम ऑयन बैटरी प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान कर रहे हैं। वे निम्न लागत वाली लिथियम ऑयन बैटरी और वैकल्पिक बैटरियों के लिए सहयोग करने हेतु कम्पलीमेंट्री स्ट्रेंथ का उपयोग कर सकते हैं। डीएसटी ने आगे सूचित किया है कि भारतीय कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए लिथियम आयन बैटरी में आद्योगिक क्षमता विकसित करने के लिए वैश्विक समझौता कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष विभाग ने सूचित किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग हेतु इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर, सरकार ने भारतीय उद्योगों को लिथियम आयन सैल विनिर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने हेतु कदम उठाए हैं।

4. फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत सरकार ने बैटरी इंजीनियरिंग हेतु केंद्र की स्थापना करने के लिए उनकी परियोजना के लिए आईआईटी, मद्रास को ₹17.20 कोरड़ का अनुदान अनुमोदित किया है।

****